The proposed Gau Seva Policy 2026 and cattle welfare and farmer support measures in Rajasthan.

Rajasthan has declared that it will roll out the **Gau Seva Policy 2026** to provide new impetus to cattle protection, promotion, and welfare in the state. The proposed policy will empower the rural livelihoods of the state, enhance the livelihoods that are cattle-based, and benefit both the farmers and the communities dominated by the population of pashu-paal under the leadership of the Chief Minister of the state, Bhajanlal Sharma. The project will play the role of enhancing livestock development, boosting the rural economy and the promotion of welfare based governance. The announcement is also in line with the larger dedication of welfare to farmers, women, youths and workers. In conjunction with this the state has emphasized that it is still in support of gaushalas, livestock schemes and direct assistance to cultivators.

The main characteristics of the intended policy are as follows:-

- A new Gau Seva Policy 2026 will be introduced in Rajasthan.
- Cattle welfare and cattle service activities in the state are the focus of the policy to speed up.
- It aims at the enhancement of Godhan and building up livestock resources.
- It should benefit the rural economy through the assistance of farmers and livestock rearers in the policy.

- It has been introduced within the broader welfare-oriented style of governance.

Current Cattle Welfare Measures.

The state has claimed that it has been over two years striving towards the direction of livestock protection, promotion and safety.

The schemes have been supported by schemes like:

- Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana.
- The Rajasthan Sahakari Gopal Credit Card Yojana is the second option.
- Mukhyamantri Dugdh Utpadak Sambal Yojana.

In registered gaushala the government makes available:

- Rs 50 per day for a large animal
- Rs 25 per day for a small animal

This financial help has been referred to as a good move towards conservation of cattle.

Farmer Support and Farming Dedication.

- Cattle welfare has also been associated with other welfare measures of farmers by the state.
- Farmers in the state are guaranteed under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi and Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana as they are given Rs 9,000 per annum.
- Approximately, it has moved an amount of about RS 11,000 crore to the bank accounts of the farmers.
- Rajasthan has budgeted this amount as agriculture in the 2026-27 financial year: Rs 1,19,408 crore.
- The government has also declared an extra bonus of 150 per quintal on top of Minimum Support Price (MSP) of wheat next year.
- Farmers will get, with this, wheat at a rate of 2735 per quintal.
- The announcement has also been made as a promise fulfilment to buy wheat at Rs 2,700 per quintal in the framework of promises of the state.

Objectives

The development of the rural economy has been strengthened.

- To provide livestock-based assistance to rural economy by making it more resilient.
- To enhance the contribution of cattle welfare in the economic activity at village level.

RASonly

Farmers and livestock rearers will also be assisted through the support program:-

- To offer institutional and financial assistance to animal rearers and farmers.
- To make animal welfare a part of agricultural security and income support.

Expanding Welfare Governance

- To incorporate animal welfare in general social welfare obligations.
- To assist vulnerable and productive components like farmers, women, youth and workers.

Conclusion

The Gau Seva Policy 2026 which is proposed is an initiative on the part of the State of Rajasthan to integrate cattle welfare, livestock development and economic empowerment of the rural population into one policy. The initiative, together with gaushala support, livestock-oriented scheme, farmer income scheme, and wheat buying incentives, is an indication of a larger program to transform animal husbandry into agricultural development and welfare-based government in the state.

MCQs(RAS Prelims)

MCQ 1: what is the principal intention of the proposed Rajasthan Gau Seva Policy 2026?

a) To substitute all the current agricultural subsidy schemes.

b) To enhance the livestock welfare, cattle growth and rural economy.

c) To privatise registered gaushalas throughout the state.

d) To cut down on the budgetary allocation on animal husbandry.

Answer : (b)

Explanation : to increase cattle welfare and service, godhan development, support farmers and livestock rearers, and boost the economy of rural areas, the proposed Gau Seva Policy 2026 has been announced.

MCQ 2: As per the announcement, what does the daily help in the registered gaushalas in Rajasthan look like?

a) 25 and 10 respectively on large and small animals.

b) big animals 40 Rs and small animals 20 Rs.

c) 50 as applied to large animals and 25 as applied to small animals.

RASonly

d) large animals- Rs 60, small animals- Rs 30.

Answer: c) large animals 50, small animals 25.

Explanation: According to the claim of the state government, a large animal in registered gaushalas and a small animal attract assistance at a rate of 50 and 25 per day respectively in the conservation process of the cattle.

MCQ 3: At the new bonus rate of MSP plus, what is the price per quintal of wheat of farmers in Rajasthan?

a) Rs 2,585

b) Rs 2,700

c) Rs 2,735

d) Rs 2,850

Answer: c)

Explanation: Under the coming year, the Chief Minister stated that farmers will get an extra bonus of 150 per quintal over MSP of wheat. Through this, the cost-effective price of wheat will be 2,735/quintal.

राजस्थान में प्रस्तावित गौ सेवा नीति 2026 तथा गौ कल्याण और किसान सहायता संबंधी उपाय

राजस्थान ने घोषणा की है कि राज्य में गौ संरक्षण, संवर्धन और कल्याण को नई गति देने के लिए **गौ सेवा नीति 2026** लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तावित यह नीति ग्रामीण आजीविका को सशक्त करेगी, गौ-आधारित अर्थगत गतिविधियों को बढ़ावा देगी तथा किसानों और पशुपालक समुदायों को लाभ पहुंचाएगी। यह पहल पशुधन विकास को प्रोत्साहित करेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी और कल्याणोन्मुख शासन को आगे बढ़ाएगी। यह घोषणा किसानों, महिलाओं, युवाओं और मजदूरों के कल्याण के व्यापक संकल्प के अनुरूप भी है। इसके साथ ही राज्य ने गौशालाओं, पशुधन योजनाओं और कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता भी दोहराई है।

प्रस्तावित नीति की प्रमुख विशेषताएँ

- राजस्थान में नई **गौ सेवा नीति 2026** लाई जाएगी।
- इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में **गौ कल्याण और गौ सेवा गतिविधियों** को तेज गति देना है।
- इसका लक्ष्य **गोधन** के विकास तथा पशुधन संसाधनों को सुदृढ़ करना है।

RASonly

- यह नीति किसानों और पशुपालकों को सहयोग देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगी।
- इसे व्यापक कल्याणोन्मुख शासन दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान गौ कल्याण उपाय

- राज्य सरकार ने कहा है कि वह दो वर्ष से अधिक समय से पशुधन संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा की दिशा में कार्य कर रही है।
- इस दिशा में जिन योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जा रही है, उनमें शामिल हैं:
  - **मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना**
  - **राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना**
  - **मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना**
- पंजीकृत गौशालाओं में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता:
  - बड़े पशु के लिए **प्रतिदिन 50 रुपये**
  - छोटे पशु के लिए **प्रतिदिन 25 रुपये**
- इस वित्तीय सहायता को गौ संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम बताया गया है।

किसान सहायता और कृषि प्रतिबद्धता

- राज्य ने गौ कल्याण को व्यापक किसान कल्याण उपायों से भी जोड़ा है।
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि** तथा **मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** के अंतर्गत राज्य के किसानों को **प्रतिवर्ष 9,000 रुपये** सुनिश्चित किए गए हैं।
- किसानों के बैंक खातों में लगभग **11,000 करोड़ रुपये** हस्तांतरित किए गए हैं।
- **वित्त वर्ष 2026-27** में राजस्थान ने कृषि के लिए **1,19,408 करोड़ रुपये** का प्रावधान किया है।

गेहूं खरीद की घोषणा

- सरकार ने आगामी वर्ष से गेहूं के **न्यूनतम समर्थन मूल्य** के अतिरिक्त **प्रति क्विंटल 150 रुपये** का बोनस देने की घोषणा की है।
- इसके बाद किसानों को गेहूं के लिए **2,735 रुपये प्रति क्विंटल** प्राप्त होंगे।
- इस घोषणा को राज्य के वादों के अंतर्गत **2,700 रुपये प्रति क्विंटल** पर गेहूं खरीद के संकल्प की पूर्ति के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है।

RASonly

उद्देश्य

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना

- पशुधन आधारित सहयोग के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनाना।
- ग्राम स्तर की आर्थिक गतिविधियों में गौ कल्याण की भूमिका को बढ़ाना।

किसानों और पशुपालकों को सहायता देना

- किसानों और पशुपालकों को संस्थागत तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- पशु कल्याण को कृषि सुरक्षा और आय सहायता से जोड़ना।

कल्याणोन्मुख शासन का विस्तार

- पशु कल्याण को व्यापक सामाजिक कल्याण दायित्वों में सम्मिलित करना।
- किसानों, महिलाओं, युवाओं और मजदूरों जैसे संवेदनशील तथा उत्पादक वर्गों को सहयोग देना।

निष्कर्ष

प्रस्तावित **गौ सेवा नीति 2026** राजस्थान सरकार का ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से गौ कल्याण, पशुधन विकास और ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को एकीकृत नीति ढाँचे में जोड़ा जा रहा है। गौशाला सहायता, पशुधन उन्मुख योजनाएँ, किसान आय समर्थन तथा गेहूं खरीद प्रोत्साहन जैसे उपाय इस बात के संकेत हैं कि राज्य पशुपालन को कृषि विकास और कल्याण आधारित शासन से जोड़ने की व्यापक दिशा में आगे बढ़ रहा है।

RASonly

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारंभिक परीक्षा)

प्रश्न 1:राजस्थान की प्रस्तावित **गौ सेवा नीति 2026** का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) सभी वर्तमान कृषि अनुदान योजनाओं को समाप्त करना
b) गौ कल्याण, पशुधन विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना
c) राज्य की सभी पंजीकृत गौशालाओं का निजीकरण करना
d) पशुपालन पर बजटीय व्यय को कम करना

उत्तर: b) गौ कल्याण, पशुधन विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना

व्याख्या: प्रस्तावित गौ सेवा नीति 2026 का उद्देश्य गौ कल्याण और गौ सेवा गतिविधियों को गति देना, गोधन के विकास को बढ़ावा देना, किसानों और पशुपालकों को सहयोग देना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

प्रश्न 2: घोषणा के अनुसार राजस्थान की पंजीकृत गौशालाओं में प्रतिदिन दी जाने वाली सहायता क्या है?

a) बड़े पशु के लिए 25 रुपये और छोटे पशु के लिए 10 रुपये
b) बड़े पशु के लिए 40 रुपये और छोटे पशु के लिए 20 रुपये
c) बड़े पशु के लिए 50 रुपये और छोटे पशु के लिए 25 रुपये
d) बड़े पशु के लिए 60 रुपये और छोटे पशु के लिए 30 रुपये

उत्तर: c) बड़े पशु के लिए 50 रुपये और छोटे पशु के लिए 25 रुपये

व्याख्या: राज्य सरकार के अनुसार पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशु के लिए प्रतिदिन 50 रुपये तथा छोटे पशु के लिए प्रतिदिन 25 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसे गौ संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी कदम माना गया है।

प्रश्न 3: नए बोनस सहित राजस्थान में किसानों को गेहूं के लिए प्रति क्विंटल कितना मूल्य मिलेगा?

a) 2,585 रुपये
b) 2,700 रुपये
c) 2,735 रुपये
d) 2,850 रुपये

उत्तर: c) 2,735 रुपये

व्याख्या: मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आगामी वर्ष से गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप किसानों को गेहूं पर कुल 2,735 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त होंगे।

RASonly

Celebration of Rajasthan Day 2026 between 14 and 19 March and the primary state celebration in Jalore.

Rajasthan will mark the Rajasthan Day 2026 in a grand style on the day of Chaitra Shukla Pratipada, and an idea of celebrating the same was taken last year by the Chief Minister Bhajanlal Sharma. Between 14 March and 19 March, the state government has arranged a program of welfare, cultural, youth, tribal, cleanliness and outreach programs throughout the state. The festivals will start with seven days of cleanliness drive and will consist of activities like the Viksit Rajasthan Run, digital quiz shows, ODOP fair and exhibition, youth conference, tribal pride event, farmer and livestock rearer interaction and beneficiary outreach. The principal day of the Rajasthan Day will be conducted in Jalore on 19 March.

Rajasthan Day Celebrations are characterized by some important features.

- The Rajasthan Day will be celebrated on the day of Chaitra Shukla Pratipada, 19 March.
- The programmes will be arranged all over the state between 14 March to 19 March.
- The events are going to be a blend of the following; the needs of the people, culture, involvement of young people, outreach to the tribes, interaction with farmers and awareness of the people.
- Both the state-level and district-level programmes will be organised.

- The central state, celebration will be at Jalore on 19 March.

Day-Wise Programme Schedule

On 14 March, the Swachhta Week begins.

- The festivities will begin with a seven days Swachhta Week.
- A state level programme in Jaipur and district level programme in all districts will be arranged.

Viksit Rajasthan Run and Public Participation Events 15 March.

- A Viksit Rajasthan Run on a state level will take place in Jaipur.
- Chief Minister Bhajanlal Sharma will be flagging off the event.
- Likewise, similar runs will be held in every district.
- The digital quiz of knowing Rajasthan will be introduced.
- An ODOP fair and exhibition inauguration on a state level will be conducted in Jaipur.
- Essays, speeches and painting contests will be done in the universities and colleges.
- Evening A five day Rajasthan Day celebration at Bikaner house, Delhi will commence.

On 16 March, the state of Rajasthan celebrates the Tribal Pride Day.

It will be held at Dungarpur at a place called Beneshwar Dham and it is called Rajasthan Janjatiya Gaurav Diwas.

The programme will include:

- base blocks in building development works.
- exhibition of tribal art and handicraft.
- interaction programmes

17 March: Youth Power Day in Rajasthan.

- Jaipur will celebrate Rajasthan Yuva Shakti Diwas.
- A youth conference at the state level will be held.
- In every district, the quiz comedic version will be known as the “Know Rajasthan quiz” will be conducted.

Evening activities will entail:

- contact with businesspersons.
- delivering employment letters in the privately-owned industry.

18 March Farmer and Livestock Rearer Prosperity Day.

- Kisan evam Pashupalak Samriddhi Diwas will be celebrated.
- Interaction with the farmers and livestock rearers will be arranged.

RASonly

- The opening of various development works will be made and foundation stone will be laid.
- Evening, In government temples throughout the state, there will be aarti.
- The Chief Minister will be involved in the Maha Aarti.

Main Rajasthan Day Function, 19 March.

- The prime main Rajasthan Day celebration will take place in Jalore.
- A beneficiary conference will be conducted.

The event will include:

- contact with beneficiaries.
- direct benefit transfer
- Cultural programme: A state level cultural programme will take place evening in Jaipur.

Purposes and Importance.

Public Welfare Outreach

- To bridge state celebrations and beneficiary-oriented government.
- To integrate festivals and development communication and participation by people.

Cultural and Social Integration:

- To promote the identity of Rajasthan by organizing cultural programmes, exhibitions as well as public events.
- to facilitate the engagement of the participation of the students, youth, tribal communities, farmers, and citizens.

Governance Visibility

- To introduce development works, outreach of beneficiaries, and state initiatives into a public platform during a period of time of at least multi-days.
- To enhance the relationship between the administration, welfare schemes, and the community participation.

Conclusion

The Day 2026 of Rajasthan can be seen as an attempt to blend the cultural identity with the welfare oriented administration. Through six days of events on cleanliness, youth, tribal communities, farmers, beneficiaries and cultural outreach, the state is transforming the Rajasthan Day into a wider platform of participation, celebration and communication concerned with development.

RASonly

MCQs (RAS Prelims)

MCQ 1: When will the annual Rajasthan Day event be held in Jalore?

a) 14 March

b) 16 March

c) 17 March

d) 19 March

Answer: d) 19 March

Explanation: The state government has fixed the main Rajasthan Day event of Jalore on 19 March, on the day of Chaitra Shukla Pratipada. Despite the fact that the programmes will begin since 14 March and continue throughout Rajasthan, the major समारooh and the beneficiary-oriented events will be held on 19 March.

MCQ 2: What are some of the events that are supposed to take place at the Beneshwar Dham Dungarpur?

a) Rajasthan Youth Power Diwali.

b) Janjatiya Gaurav Diwas, Rajasthan.

c) Viksit Rajasthan Run

d) Cultural evening on the state level.

Answer : b) Rajasthan Janjatiya Gaurav Diwas.

Explanation : The dungarpur Rajasthan Janjat Gaurav Diwas is the programme at Beneshwar Dham on 16 March. It is structured on tribal outreach and comprises of development-associated foundation ceremonies, tribal art and handicraft exhibitions, and interaction programmes. Jaipur is the venue of the youth event and the main cultural programme is different.

MCQ 3: Which one of the following is properly matched?

a) 15 March -Maha Aarti at government temples.

b) 18 March, Kisan evam Pashupalak Samriddhi Diwas.

c) 16 March Main Rajasthan Day celebration in Jalore.

d) 17 March -Swachhta Week starts.

Answer : b) 18 March Kisan evam Pashupalak Samriddhi Diwali.

Explanation : The schedule indicates categorically that 18 March is going to be Kisan evam Pashupalak Samriddhi Diwas where farmers and livestock rearers will be

RASonly

involved and development works will be inaugurated or launched. Swachhta Week starts on 14 March, the main function in the Jalore is on 19 March and the youth activities is on 17 March. Organized as the uploaded article format.

14 से 19 मार्च के बीच राजस्थान दिवस 2026 का आयोजन तथा जालोर में मुख्य राज्य स्तरीय समारोह

राजस्थान दिवस 2026 का आयोजन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर भव्य रूप से किया जाएगा। इस परंपरा की शुरुआत पिछले वर्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर की गई थी। इस बार राज्य सरकार ने 14 मार्च से 19 मार्च तक पूरे प्रदेश में जनकल्याण, संस्कृति, युवा सहभागिता, जनजातीय गौरव, स्वच्छता और जनसंपर्क से जुड़े विविध कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इन आयोजनों की शुरुआत सात दिवसीय स्वच्छता सप्ताह से होगी। कार्यक्रमों में विकसित राजस्थान दौड़, राजस्थान को जानें प्रश्नोत्तरी, एक जिला एक उत्पाद मेला एवं प्रदर्शनी, युवा सम्मेलन, जनजातीय गौरव आयोजन, किसान और पशुपालक संवाद तथा लाभार्थी सम्मेलन जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। राजस्थान दिवस का मुख्य राज्य स्तरीय समारोह 19 मार्च को जालोर में आयोजित किया जाएगा।

राजस्थान दिवस समारोह की प्रमुख विशेषताएँ

- राजस्थान दिवस का आयोजन **19 मार्च** को **चैत्र शुक्ल प्रतिपदा** के अवसर पर किया जाएगा।
- कार्यक्रमों का आयोजन **14 मार्च से 19 मार्च** तक पूरे प्रदेश में किया जाएगा।
- इन आयोजनों में **जनकल्याण, संस्कृति, युवा भागीदारी, जनजातीय संपर्क, किसान संवाद और नागरिक जागरूकता** का समावेश होगा।
- **राज्य स्तरीय** तथा **जिला स्तरीय** दोनों प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- **मुख्य राज्य स्तरीय समारोह 19 मार्च** को **जालोर** में होगा।

दिनवार कार्यक्रम

14 मार्च: स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत

- कार्यक्रमों की शुरुआत **सात दिवसीय स्वच्छता सप्ताह** से होगी।
- **जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम** तथा **सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम** आयोजित किए जाएंगे।

15 मार्च: विकसित राजस्थान दौड़ और जनभागीदारी कार्यक्रम

- **जयपुर में राज्य स्तरीय विकसित राजस्थान दौड़** आयोजित की जाएगी।
- इस दौड़ को **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे**।
- इसी प्रकार सभी जिलों में भी विकसित राजस्थान दौड़ आयोजित होगी।
- **राजस्थान को जानें** प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया जाएगा।
- **जयपुर में एक जिला एक उत्पाद मेला एवं प्रदर्शनी** का राज्य स्तरीय उद्घाटन होगा।

RASonly

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में **निबंध, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएँ** आयोजित की जाएंगी।
- शाम को **दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में पाँच दिवसीय राजस्थान दिवस उत्सव** का शुभारंभ होगा।

16 मार्च: राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस

- **डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम** में **राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस** मनाया जाएगा।
- कार्यक्रम के अंतर्गत:
  - विकास कार्यों का **शिलान्यास**
  - **जनजातीय कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी**
  - **संवाद कार्यक्रम**
    आयोजित किए जाएंगे।

17 मार्च: राजस्थान युवा शक्ति दिवस

- **जयपुर में राजस्थान युवा शक्ति दिवस** मनाया जाएगा।
- **राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन** आयोजित होगा।
- सभी जिलों में **राजस्थान को जानें प्रश्नोत्तरी** आयोजित की जाएगी।
- शाम को:
  - **उद्यमियों के साथ संवाद**
  - **निजी क्षेत्र में रोजगार पत्रों का वितरण**
    जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे।

18 मार्च: किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस

- **किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस** मनाया जाएगा।
- किसानों और पशुपालकों के साथ **संवाद कार्यक्रम** आयोजित होंगे।
- विभिन्न **विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास** किया जाएगा।
- शाम को प्रदेशभर के **राजकीय मंदिरों में आरती** आयोजित होगी।
- **मुख्यमंत्री महाआरती में शामिल होंगे**।

19 मार्च: मुख्य राजस्थान दिवस समारोह

- **राजस्थान दिवस का मुख्य राज्य स्तरीय समारोह जालोर** में आयोजित होगा।
- इस अवसर पर **लाभार्थी सम्मेलन** होगा।
- कार्यक्रम में:
  - **लाभार्थियों के साथ संवाद**

RASonly

  - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण**
    किया जाएगा।

- शाम को **जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम** आयोजित होगा।

उद्देश्य और महत्व

जनकल्याणकारी जनसंपर्क

- राज्य स्तरीय उत्सवों को **लाभार्थी आधारित शासन** से जोड़ना।
- पर्व और उत्सवों को **विकास संवाद** तथा **जनभागीदारी** के साथ जोड़ना।

सांस्कृतिक और सामाजिक एकीकरण

- सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शिनियों और सार्वजनिक आयोजनों के माध्यम से **राजस्थान की पहचान को सशक्त करना**।
- **विद्यार्थियों, युवाओं, जनजातीय समुदायों, किसानों और आम नागरिकों** की भागीदारी बढ़ाना।

शासन की दृश्यता

- विकास कार्यों, लाभार्थी संपर्क और राज्य की पहलों को **बहुदिवसीय सार्वजनिक मंच** पर प्रस्तुत करना।
- प्रशासन, कल्याणकारी योजनाओं और समुदाय की भागीदारी के बीच **संबंध को मजबूत करना**।

निष्कर्ष

राजस्थान दिवस 2026 का यह आयोजन सांस्कृतिक पहचान और जनकल्याणकारी शासन को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। स्वच्छता, युवा, जनजातीय समुदाय, किसान, लाभार्थी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को एक ही श्रृंखला में शामिल कर राज्य सरकार राजस्थान दिवस को केवल उत्सव नहीं, बल्कि सहभागिता, विकास संवाद और जनसंपर्क का व्यापक मंच बना रही है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारंभिक परीक्षा)

प्रश्न 1: जालोर में राजस्थान दिवस का मुख्य समारोह किस तिथि को आयोजित किया जाएगा?

(क) 14 मार्च
(ख) 16 मार्च
(ग) 17 मार्च
(घ) 19 मार्च

उत्तर: (घ) 19 मार्च

व्याख्या: राज्य सरकार ने राजस्थान दिवस का मुख्य राज्य स्तरीय समारोह 19 मार्च को जालोर में आयोजित करने का निर्णय लिया है। यद्यपि कार्यक्रमों की शुरुआत 14 मार्च से हो जाएगी और वे पूरे प्रदेश में चलेंगे, फिर भी मुख्य समारोह, लाभार्थी सम्मेलन और प्रमुख आयोजन 19 मार्च को ही होंगे।

RASonly

प्रश्न 2: बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में निम्न में से कौन-सा आयोजन किया जाएगा?

(क) राजस्थान युवा शक्ति दिवस
(ख) राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस
(ग) विकसित राजस्थान दौड़
(घ) राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या

उत्तर: (ख) राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस

व्याख्या: 16 मार्च को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन जनजातीय समुदायों के सम्मान और सहभागिता से जुड़ा है। इसके अंतर्गत विकास कार्यों का शिलान्यास, जनजातीय कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी तथा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

प्रश्न 3: निम्न में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?

(क) 15 मार्च — राजकीय मंदिरों में महाआरती
(ख) 18 मार्च — किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस
(ग) 16 मार्च — जालोर में मुख्य राजस्थान दिवस समारोह
(घ) 17 मार्च — स्वच्छता सप्ताह का आरंभ

उत्तर: (ख) 18 मार्च — किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस

व्याख्या: कार्यक्रमों की निर्धारित रूपरेखा के अनुसार 18 मार्च को किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन किसानों और पशुपालकों से संवाद, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास तथा शाम को राजकीय मंदिरों में आरती आयोजित की जाएगी। स्वच्छता सप्ताह 14 मार्च से शुरू होगा, मुख्य समारोह 19 मार्च को जालोर में होगा और युवा शक्ति दिवस 17 मार्च को मनाया जाएगा।

RASonly

70-seat Assembly reconstitution in Rajasthan following the delimiting process and the associated legislative readiness.

The next Census can have a profound effect on the political landscape of Rajasthan as a result of delimitation. The State Assembly Speaker Vasudev Devnani suggested that the State Assembly strength could increase by a figure of 70 and the total strength will be 200-270. Should such a thing occur, it would become the first increase since 1977. This was indicated during a programme that was conducted at the Constitution Club. The given expansion is not only significant in terms of the representation in elections but also in terms of the legislature operation, as the current Assembly room is planned to accommodate only 200 members. The development can also expand the reserved seats and also free up space to new political leadership in the state.

Key Development

- Indicating that post delimitation, the Assembly seats of the state of Rajasthan could increase by 70 seats, the Assembly Speaker of the state of Rajasthan referred to as Vasudev Devnani.
- Provided this is done, the overall strength of the Rajasthan Legislative Assembly would be raised to 270, which is currently 200.
- This would be the Assembly seat increase since 1977.
- The statement was given at an event held at the Constitution Club.

- The indication is associated with the anticipated process of delimitation of census post-2011.

Why This Matters

- An increase in seats would restructure the political structure of representation of Rajasthan.
- The increased number of seats would allow a chance to bring new leaders to the Assembly.
- It is also possible that the amount of seats allocated to the is also subject to increase of the seats allocated to the reserved categories.
- The modification would involve an increase in the seating/infrastructure capacity of the Assembly.

The Rajasthan Assembly Seats have a historical background.

- In the first Assembly elections of 1952, Rajasthan had 160 seats.
- This was changed to a total of 167 seats in 1957.
- In 1967, the strength was increased by 8 seats making it reach 184.
- In 1977 the Assembly seats were redistributed to 200.
- The Rajasthan Assembly seats have not varied at all in the last 49 years since 1977.

Legislation and the Preparation of the Future.

- The current Assembly house has seating capacity of just 200 MLAs.
- Devnani reported that the seating capacity of House would be increased with consideration of the future requirements.
- The simple outline of the expansion is prepared, and the interior work has not been done.
- The Assembly complex also proposes a variety of projects that include a Central Hall on the pattern of Parliament.
- The Central Hall will have an expectation of having tea, snacks and meals.
- where delimitation suggests increase prior to the elections of the year 2028, another hall can be ready on the same design as the current chamber.

Rajasthan Assembly Highlights of the Fifth Session.

Duration of Proceedings

- There were 24 sittings in the fifth session.
- The discussions took approximately 184 hours to happen.

Debate Participation

In the dissertation on the Motion of Thanks on the Governor's Address:

- BJP: 13 hours 14 minutes

RASonly

- Congress: 10 hours 52 minutes
- Other parties: 1 hour 37 minutes

In the general debate:

- BJP: 9 hours 42 minutes
- Congress: 8 hours 19 minutes
- Other parties: 1 hour 21 minutes

Questions Received

- There were a total of 8,919 questions received during the fifth session.

These included:

- 4,311 starred questions
- 4,603 unstarred questions
- 5 short-notice questions
- Of the marked questions, 440 were enumerated, 232 orally asked and answered.
- There were also 451 unmarked questions.
- In the previous 4 sessions, a state government responded to between 22,074 out of 22,735 questions.

Bills and Budget Discussion

- There were 10 Bills that were introduced and passed in the session.
- 202627 budget estimates were discussed over four days in general.
- 84 MLAs were in attendance in the general budget discussion.
- Out of a total of 64 grant requests, 16 demands were to be discussed during 8 days.
- The received information in this regard was, that there were received, with respect to the House, in total, 3,935 cut motions, of which 3,599 had been moved.

Conclusion

The potential rise of 70 Assembly seats by way of delimitation may emerge to be one of the biggest institutional transformations in the politics of Rajasthan in decades. It would increase representation, change the social and political balance in House, and would need to make significant changes in the legislative infrastructure. Meanwhile, the debate has also revived the discussion of the Assembly seat increase over the years, as well as the readiness of the state to have a larger legislature in coming years.

RASonly

MCQs (RAS Prelims)

MCQ 1: Assuming that there are 70 more seats of Rajasthan Assembly after delimitation, then how many seats will the Assembly have?

a) 250

b) 260

c) 270

d) 280

Answer: c) 270

Explanation: There are 200 Assembly seats in Rajasthan. According to Speaker Vasudev Devnani, delimitation can imply the addition of 70 extra seats. As such, the total strength was going to increase to 270. This was a significant projected increase since it would represent the first increase in the number of Assembly seats since 1977.

MCQ 2: What is the chronological order of the Assembly seat strength of Rajasthan?

a) 160 in 1952, 167 in 1957, 184 in 1967, 200 in 1977

b) 167 in 1952, 160 in 1957, 184 in 1967, 200 in 1977

c) 160 in 1952, 184 in 1957, 167 in 1967, 200 in 1977

d) 184 in 1952, 167 in 1957, 160 in 1967, 200 in 1977

Answer: a) 160 in 1952, 167 in 1957, 184 in 1967, 200 in 1977

Explanation : The article provides a historical sequential account of Assembly seats in Rajasthan. There were 160 seats in the first election in 1952. This was followed by 167 in 1957, 184 in 1967 and lastly 200 in 1977. Nothing further has subsequently increased, and this is why the proposed delimitation change is politically relevant.

MCQ 3: What does the fifth session of the Rajasthan Assembly correct the following statements?

a) 18 sittings and 10 Bills withdrawn.

b) It sat 24 times and introduced 10 Bills, which it passed.

c) It sat two dozen times and passed 16 Bills.

d) It sat 32 times and introduced and passed 8 Bills.

Answer : b) It sat 24 times and 10 Bills introduced and passed.

RASonly

Explanation: The fifth session of the Rajasthan Assembly had 24 sittings and approximately 184 hours of discussion according to the report. It also documented that 10 Bills were presented and enacted. This makes option b correct. The other alternatives either vary the number of sittings or the number and the status of Bills hence they do not correspond to the report.

परिसीमन प्रक्रिया के बाद राजस्थान में विधानसभा की 70 सीटें बढ़ने की संभावना तथा उससे जुड़ी विधायी तैयारियाँ

अगली जनगणना के बाद होने वाला परिसीमन राजस्थान की राजनीतिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष **वासुदेव देवनानी** ने संकेत दिया कि राजस्थान विधानसभा की कुल शक्ति में **70 सीटों** की वृद्धि हो सकती है, जिससे कुल संख्या **200 से बढ़कर 270** हो जाएगी। यदि ऐसा होता है, तो यह **1977 के बाद पहली वृद्धि** होगी। यह संकेत **संविधान क्लब** में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया। यह संभावित विस्तार केवल चुनावी प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विधानमंडल के संचालन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान विधानसभा कक्ष केवल **200 सदस्यों** के बैठने के लिए निर्मित है। यह परिवर्तन आरक्षित सीटों की संख्या को भी प्रभावित कर सकता है और राज्य में नए राजनीतिक नेतृत्व के लिए अवसर भी खोल सकता है।

प्रमुख विकास

- राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष **वासुदेव देवनानी** ने संकेत दिया कि परिसीमन के बाद राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या **70** बढ़ सकती है।
- यदि यह लागू होता है, तो राजस्थान विधानसभा की कुल शक्ति **200 से बढ़कर 270** हो जाएगी।
- यह **1977 के बाद पहली बार** विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि होगी।
- यह संकेत **संविधान क्लब** में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया।
- यह संभावना आगामी **जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया** से जुड़ी हुई है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

- सीटों की संख्या बढ़ने से राजस्थान की **राजनीतिक प्रतिनिधित्व संरचना** में बदलाव आएगा।
- अधिक सीटें होने से **नए नेताओं** को विधानसभा में आने का अवसर मिलेगा।
- **आरक्षित वर्गों** के लिए निर्धारित सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है।
- इस परिवर्तन के कारण विधानसभा की **बैठक क्षमता और आधारभूत संरचना** का विस्तार करना पड़ेगा।

RASonly

राजस्थान विधानसभा सीटों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **1952** के प्रथम विधानसभा चुनाव में राजस्थान में **160 सीटें** थीं।
- **1957** में यह संख्या बढ़कर **167** हो गई।
- **1967** में **8 सीटों** की वृद्धि हुई और कुल संख्या **184** हो गई।
- **1977** में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर **200** कर दी गई।
- **1977** के बाद से पिछले **49 वर्षों** में राजस्थान विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

विधायी आधारभूत संरचना और भावी तैयारी

- वर्तमान विधानसभा कक्ष में केवल **200 विधायकों** के बैठने की क्षमता है।
- देवनानी ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सदन की बैठक क्षमता बढ़ाई जाएगी।
- विस्तार की **मूल संरचना** तैयार है, जबकि **आंतरिक कार्य** अभी शेष है।
- विधानसभा परिसर में **संसद की तर्ज पर एक केंद्रीय सभा कक्ष** बनाने का भी प्रस्ताव है।
- इस केंद्रीय सभा कक्ष में **चाय, अल्पाहार और भोजन** की व्यवस्था होने की अपेक्षा है।
- यदि **2028 के चुनावों** से पहले परिसीमन के कारण सीटें बढ़ती हैं, तो वर्तमान कक्ष की तर्ज पर एक अतिरिक्त सभा कक्ष भी तैयार किया जा सकता है।

राजस्थान विधानसभा के पाँचवें सत्र की मुख्य विशेषताएँ

कार्यवाही की अवधि

- पाँचवें सत्र में कुल **24 बैठकें** हुईं।
- चर्चाएँ लगभग **184 घंटे** चलीं।

वाद-विवाद में भागीदारी

- **राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव** की चर्चा में:
  - **भारतीय जनता पार्टी:** 13 घंटे 14 मिनट
  - **कांग्रेस:** 10 घंटे 52 मिनट
  - **अन्य दल:** 1 घंटा 37 मिनट
- **सामान्य चर्चा** में:
  - **भारतीय जनता पार्टी:** 9 घंटे 42 मिनट
  - **कांग्रेस:** 8 घंटे 19 मिनट
  - **अन्य दल:** 1 घंटा 21 मिनट

RASonly

प्राप्त प्रश्न

- पाँचवें सत्र में कुल **8,919 प्रश्न** प्राप्त हुए।
- इनमें शामिल थे:
    - **4,311 तारांकित प्रश्न**
    - **4,603 अतारांकित प्रश्न**
    - **5 अल्पसूचना प्रश्न**
- तारांकित प्रश्नों में से **440 सूचीबद्ध** हुए, जिनमें **232 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गए और उनके उत्तर दिए गए**।
- **451 अतारांकित प्रश्न** भी सूचीबद्ध हुए।
- पिछले **चार सत्रों** में राज्य सरकार ने **22,735 प्रश्नों में से 22,074 प्रश्नों** के उत्तर दिए।

विधेयक और आय-व्यय अनुमान पर चर्चा

- सत्र में कुल **10 विधेयक** प्रस्तुत किए गए और पारित हुए।
- **2026-27 के आय-व्यय अनुमान** पर सामान्य चर्चा **चार दिनों** तक चली।
- सामान्य बजट चर्चा में **84 विधायक** शामिल हुए।
- कुल **64 अनुदान मांगों** में से **16 मांगों** पर **8 दिनों** तक चर्चा निर्धारित की गई।
- कुल **3,935 कटौती प्रस्तावों** की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से **3,599 प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए गए**।

निष्कर्ष

परिसीमन के माध्यम से विधानसभा सीटों में **70 की संभावित वृद्धि** राजस्थान की राजनीति में पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी संस्थागत परिवर्तनों में से एक सिद्ध हो सकती है। इससे प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ेगा, सदन की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में परिवर्तन आएगा, और विधायी आधारभूत संरचना में बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी। साथ ही, इस चर्चा ने विधानसभा सीटों की ऐतिहासिक वृद्धि और भविष्य में बड़े विधानमंडल के लिए राज्य की तैयारियों को भी केंद्र में ला दिया है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारंभिक परीक्षा)

प्रश्न 1: यदि परिसीमन के बाद राजस्थान विधानसभा में 70 सीटें और बढ़ती हैं, तो विधानसभा की कुल शक्ति कितनी हो जाएगी?

a) 250
b) 260
c) 270
d) 280

RASonly

उत्तर: c) 270

व्याख्या: विवरण के अनुसार वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संकेत दिया कि परिसीमन के बाद 70 अतिरिक्त सीटें जुड़ सकती हैं। इस प्रकार कुल शक्ति बढ़कर 270 हो जाएगी। यह संभावित वृद्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1977 के बाद पहली बार विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी।

प्रश्न 2: राजस्थान विधानसभा सीटों की संख्या का सही कालक्रम क्या है?

a) 1952 में 160, 1957 में 167, 1967 में 184, 1977 में 200
b) 1952 में 167, 1957 में 160, 1967 में 184, 1977 में 200
c) 1952 में 160, 1957 में 184, 1967 में 167, 1977 में 200
d) 1952 में 184, 1957 में 167, 1967 में 160, 1977 में 200

उत्तर: a) 1952 में 160, 1957 में 167, 1967 में 184, 1977 में 200

व्याख्या: विवरण में राजस्थान विधानसभा सीटों की ऐतिहासिक प्रगति स्पष्ट रूप से दी गई है। 1952 के प्रथम चुनाव में 160 सीटें थीं। इसके बाद 1957 में संख्या 167 हुई, 1967 में 184 हुई और 1977 में बढ़कर 200 हो गई। इसके बाद कोई वृद्धि नहीं हुई, इसलिए प्रस्तावित परिसीमन राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रश्न 3: राजस्थान विधानसभा के पाँचवें सत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

a) इसमें 18 बैठकें हुईं और 10 विधेयक वापस ले लिए गए
b) इसमें 24 बैठकें हुईं और 10 विधेयक प्रस्तुत होकर पारित हुए
c) इसमें 24 बैठकें हुईं और 16 विधेयक पारित हुए
d) इसमें 32 बैठकें हुईं और 8 विधेयक प्रस्तुत होकर पारित हुए

उत्तर: b) इसमें 24 बैठकें हुईं और 10 विधेयक प्रस्तुत होकर पारित हुए

व्याख्या: विवरण के अनुसार राजस्थान विधानसभा के पाँचवें सत्र में 24 बैठकें हुईं और लगभग 184 घंटे चर्चा चली। इसी सत्र में 10 विधेयक प्रस्तुत किए गए और पारित हुए। इसलिए विकल्प b सही है। अन्य विकल्पों में या तो बैठकों की संख्या बदल दी गई है या विधेयकों की संख्या तथा स्थिति गलत बताई गई है।

RASonly

RASonly